टीबी से जंग – दो वक्त को रोटी से बदल सकती है तस्वीर

प्रदीप सुरीन | Jan 30, 2017, 21:14 IST

सिम्बोलिक इमेज।

नई दिल्ली । अभी कुछ दिन पहले मेरे घर में एक महिला घरेलू काम करने के लिए आई। मैंने उससे सामान्य पूछताछ के अलावा एक ऐसा सवाल पूछा जो आमतौर पर कोई जानना नहीं चाहता। मैं जानना चाहता था कि वह महिला टीबी संक्रमित है कि नहीं। जब उसने घर में काम करना शुरु किया तो एक दिन मैं उसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले गया और टीबी की जांच कराई। कुछ दिनों बाद जब रिपोर्ट लेने गया तो पता चला कि महिला टीबी संक्रमित है। पौष्टिक भोजन की कमी और गरीबी टीबी की समस्या को और गंभीर बनाती जा रही है।

Advertisement
START NOW
Login to Your Account
Sign In and Check Your Email

मसला यहां खत्म नहीं होता। सामान्य टीबी और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट-टीबी (एमडीआर-टीबी) पहले ही देश के लिए बड़ी समस्याएं रही है। लेकिन पिछले सात-आठ सालों में एक्सट्रिमली ड्रग रेजिस्टेंट-टीबी (एक्सडीआर-टीबी) और एक्सट्रिमली – एक्सट्रिमली ड्रग रेजिस्टेंट-टीबी (एक्सएक्सडीआर-टीबी) के बढ़ती संख्या आने वाले सालों में हर नागरिक और सरकार के लिए समस्या पैदा करने के लिए तैयार खड़ी हैं।

गरीबी और पौष्टिक आहार पर आगे बढ़ने से पहले एक मुख्य बिंदू पर चर्चा करने की जरुरत है। पिछले साल ब्रिटेन की प्रतिष्ठित मेडिकल पत्रिका "लैंसेट" ने आंखें खोली है। वैज्ञानिकों ने भारत में टीबी की दवाओं के खपत को आधार बनाते हुए कई तथ्यों को सामने रखा है। मसलन, सरकार हमेशा मानती रही है कि देश के ज्यादातर टीबी मरीज सरकारी अस्पतालों में इलाज कराते हैं। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा कुल 35 लाख टीबी में से केवल 14 लाख मरीज सरकार अस्पतालों में इलाज के लिए जाते हैं। जबकि लगभग 22 लाख टीबी मरीज निजी अस्पतालों में इलाज के लिए जा रहे हैं। शोध में कहा गया है कि टीबी के इलाज में सरकारी और निजी अस्पतालों में अलग-अलग तरीके से उपचार करने से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के और गंभीर होने की आशंका बढ़ गई है। इसकी भनक इस बात से भी साफ होती है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की ओर से जारी ताजा ग्लोबल टीबी रिपोर्ट -2016 के अनुसार भारत में लगभग 3,048 ऐसे मरीज हैं जिन्हें लैब टेस्ट में एक्सडीआर-टीबी संक्रमित पाया गया है। तस्वीर बेहद साफ है कि गलत इलाज के कारण ही दवाओं के निष्क्रिय होने के मामले बढ़े हैं। इसमें निजी अस्पतालों के भूमिका को दरकिनार नहीं किया जा सकता। हाल ही में केंद्र सरकार ने लगभग 600 मरीजों को बडाक्विलीन नाम की नई दवा उपलब्ध कराने का फैसला किया जो एक्सएक्सडीआर-टीबी से संक्रमित हैं। मुंबई में एक अंतरराष्ट्रीय संस्था डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर (एमएसएफ) ने भी लगभग 70 गरीब टीबी मरीजों को ऐसी दवाएं उपलब्ध कराई है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही है कि बाकि बचे मौजूदा एक्सएक्सडीआर-टीबी संक्रमित मरीजों का क्या होगा?

अब असल मुद्दे पर आते हैं। क्या आम टीबी मरीजों को राशन उपलब्ध कराने से
संक्रमण में कमी आ सकती है। इसका जवाब हां है। इस तथ्य को सही साबित करने के लिए हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) ने एक शोध किया है। काफी सरल शब्दों में वैज्ञानिकों से समझाया कि अगर किसी व्यक्ति को टीबी होता है तो उसका वजन घटने लगता है। यही कम वजन होना टीबी के संक्रमण को बढ़ाने में मददगार होता है। देश में टीबी संक्रमित 15-19 वर्ष के किशोरों पर की गई एक स्टडी में यह बात भी सामने आई कि इनमें से दो-तिहाई कुपोषित थे। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि देश में लगभग 50 प्रतिशत टीबी संक्रमितों की मुख्य वजह कुपोषण ही रही है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में लगभग 1695 टीबी संक्रमित व्यस्कों पर किए अध्ययन में पता चला कि इनमे से 90 फीसदी एक हद तक कुपोषण के शिकार हैं। आईसीएमआर ने भी इस शोध को लेकर सुझाया है कि देश में टीबी पर लगाम कसने के लिए मरीजों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना ही होगा।

ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार इस गंभीर समस्या से अवगत नहीं है। पिछले पांच सालों में खुद केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ तालमेल कर टीबी मरीजों को राशन उपलब्ध कराने के कई तरीके निकाले हैं। पर केंद्र सरकार अभी भी टीबी मरीजों को राशन उपलब्ध कराने या फिर पैसा देने के मुद्दे पर ही फंसी नजर आ रही है। विभिन्न घटकों का कहना है कि अलग-अलग भौगोलिक परिवेश के कारण एक ही तरह का राशन फायदेमंद नहीं रहेगा। इसीलिए मरीजों को पैसा दिया जाए ताकि वे अपने मर्जी के मुताबिक भोजन खरीद सकें। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का यह भी मत है कि पैसा मिलने पर मरीज राशन की जगह बेजा इस्तेमाल न कर ले। इस बीच देश के अलग-अलग जगह पायलट प्रोजेक्ट के तहत मरीजों को टोकन देने जैसी व्यवस्था सटीक साबित हो रही है। इसके तहत टीबी मरीजों के इलाज शुरु होते ही उन्हे टोकन दिया जाता है। इसे लेकर दवा दुकानों से दवाएं मिलती है। यहां से दूसरा टोकन जारी किया जाता है जो मरीजों को अन्य दुकानों से राशन दिलाता है। पड़ोसी देश बांग्लादेश और लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील टीबी मरीजों को हर महीने पौष्टिक आहार खरीदने के लिए सीधे बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर करते हैं। रूस जैसे विकसित देश भी टीबी मरीजों को न सिर्फ गर्म खाना उपलब्ध करता है, बल्कि राशन, पैसा और पहनने को कपड़े भी देता है। मलावी, पेरू और कंबोडिया सरकार भी ऐसी ही योजनाएं चलाती है।

कुल मिलाकर हमें एक ऐसी व्यवस्था तैयार करनी होगी जिसके तहत देश के सभी निजी अस्पतालों में टीबी का इलाज करा रहे मरीजों पर सरकार की नजर रहे। ताकि दिशा-निर्देशों के तहत ही मरीजों को दवाएं उपलब्ध हो। साथ ही अब केंद्र सरकार को बिना किसी देरी के टीबी संक्रमितों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने पर विचार करने की जरुरत है।

पोस्ट-स्क्रिप्ट: मैंने कई निजी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे टीबी केंद्रों का दौरा किया और पाया कि राशन मिलने से मरीजों के सेहत में काफी सुधार है। कई एक्सएक्सडीआर-टीबी मरीजों से मिला जो मौत के मुंह से बाहर आ चुके हैं या फिर आने के बेहद करीब हैं। मुफ्त राशन उनके लिए जीवनदान बना है।

(एमएसएफ फेलोशिप के तहत)